आकाशवाणी शिमला

14.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00 बजे

मुख्यमंत्री

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण ने प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों में लगभग एक हजार 7 सौ 34 करोड़ 65 लाख रूपए का निवेश और 5 हजार 3 सौ 88 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रस्ताव में कौशल–वार रोजगार का विवरण शामिल होना चाहिए और श्रम–प्रधान व हरित उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर एक महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा ताकि लोगों को सुलभ व कैशलैस सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अस्पतालों में टेस्ट की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें गुणात्मक व निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास व विस्तार पर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है।

अनिरूद्ध सिंह

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बीते कुछ वर्षों के दौरान हो रही प्राकृतिक आपदाओं से सरकार चिंतित है और लगातार बेहतर आपदा प्रबंधन में जुटी है। शिमला में आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनिकरण दिवस पर चार दिवसीय समर्थ प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों का जागरूक होना बेहद आवश्यक है ताकि नुकसान कम हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव में देरी को बेवजह मुददा बना रही है। जबकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि पंचायती राज चुनाव समय पर ही होंगे।

पैंशनर

हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट पैंशनर फ्रंट ने पैंशन न मिलने, 2016 से एरियर का भुगतान न होने और डीए व मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर आज शिमला में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ज्वाइंट पैशनर फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पैंशनरों को समय पर पैंशन नहीं मिल रही है और नए वेतनमान का एरियर भी 2016 से लम्बित है उन्होंने कहा कि अब पैंशनरों के सब्र का बांध टूट गया है और आज जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए गए हैं। आत्माराम शर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने पैंशनरों की मांगों को लेकर जल्द संयुक्त समन्वय समिति कर गठन का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सरकारी कर संग्रह

मौजूदा वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 11 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने बताया है कि इस वर्ष पहली अप्रैल से 12 अक्टूबर तक कॉर्पोरेट कर संग्रह लगभग 5 लाख 2 हजार करोड़ रुपए रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4 लाख 29 हजार करोड़ रुपये था। आयकर विभाग के अनुसार प्रतिभूति लेनदेन पर कर संग्रह 30 हजार आठ सौ 78 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 30 हजार छह सौ 30 करोड़ रुपये था।

———————————————————————————————————